9 जुलाई, 2015

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक: आगे की राह

*डॉ. राहुल मिश्रा**

29 जून, 2015 को भारत सहित कुल 50 देशों के प्रतिनिधियों ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। यह एक एशियाई वित्तीय संस्थान स्थापित करने की दिशा में अति गुंजायमान चीनी पहल है, जिसका उद्देश्य इसके सदस्य देशों में अवसंरचना सुदृढ़ करना और सदस्य देशों के बीच अंतरा-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर-क्षेत्रीय थल, वायु एवं समुद्री संपर्क विकसित करना है, जिससे सदस्य देशों के बीच एक अबाधित परस्पर-संपर्क क्षेत्र बन सके। यह करार बहुपक्षीय बैंक की स्थापना की कानूनी रूपरेखा को साकार करता है, जो पश्चिम-संचालित तथा उनके प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थाओं का स्थायी विकल्प प्रदान करने की बहुप्रतिक्षित सोच (विज़न) पर आधारित है।

100 अरब अमरीकी डॉलर की प्राधिकृत पूंजी से स्थापित इस बैंक के सदस्यों के समूह में सात और सदस्यों के जुड़ने की संभावना है, जिससे इसके सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 57 हो जाएगी। वास्तव में, इस करार के हस्ताक्षर समारोह में कुल 57 देशों की उपस्थिति दर्ज हुई। इस करार पर औपचारिक हस्ताक्षर होने से वर्ष 2015 के अंत में इस बैंक के खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सदस्य देशों ने इस बैंक की स्थापना चीन में करने पर अपनी सहमति दे दी है और इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग में होगा।

पृष्ठभूमिः संरचना, कार्य पद्धति और संयोजन

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) एक क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है जिसका प्रस्ताव सबसे पहले चीन ने किया था। इसका मुख्य कार्य विकासशील तथा अल्पविकसित एशियाई देशों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए सुविधा प्रदान करना होगा। यद्यपि इस बैंक (की स्थापना) का विचार चीनी नेतृत्व द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2013 में चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग और राष्ट्रपति शी झिनपिंग की दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की यात्रा के दौरान दिया गया, तथापि, एक क्षेत्रीय अवसंरचना बैंक स्थापित करने के

विचार को चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा अप्रैल 2014 में एशिया बोआओ मंच पर अपने भाषण के दौरान आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा, "चीन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की तैयारियों के संबंध में एशिया तथा एशिया के बाहर संगत पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श में तेजी लाने के लिए तैयार है और आशा करता है कि इस बैंक की जल्दी से जल्दी आधिकारिक रूप से शुरूआत हो सके।"[1]

परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2014 में 26वें वार्षिक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीइटी) शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले 22 एशियाई देशों ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नवम्बर 2014 में संभावित संस्थापक सदस्यों (पीएफएम) ने चीन के कुनमिंग में प्रमुख वार्ताकारों की प्रथम बैठक (सीएनएम) में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की संभावना पर विचार-विमर्श किया। मुम्बई में जनवरी 2015 में संपन्न प्रमुख वार्ताकारों की द्वितीय बैठक (सीएनएम) के दौरान करार के अनुच्छेद (एओए) प्रस्तुत किए गए। इस करार के अनुच्छेद (एओए) पर मार्च 2015 में कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न प्रमुख वार्ताकारों की तीसरी बैठक (सीएनएम) और अप्रैल 2015 में बीजिंग में प्रमुख वार्ताकारों की चौथी बैठक (सीएनएम) में और भी विचार-विमर्श किया गया। मई 2015 में सिंगापुर में प्रमुख वार्ताकारों की पांचवीं बैठक (सीएनएम) में करार के अनुच्छेद (एओए) पर चर्चाओं को अंतिम रूप दिया गया।[2] इन प्रारंभिक चर्चाओं के फलस्वरूप, अंतिम रूप से तैयार करार पर 29 जून, 2015 को हस्ताक्षर किया गया। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का एक चीनी पहल से 'वैश्विक सदस्यता के साथ चीन के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय संस्था' में सफल अंतरण 29 जून, 2015 को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के साथ पूर्ण हुआ प्रतीत होता है।[3]

चीन में मुख्यालय वाले इस बैंक में 50 संस्थापक सदस्य, सात संभावित संस्थापक सदस्य (पीएफएम) (डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और थाइलैंड) तथा तीन आवेदक नामतः हाँगकाँग, हंगरी और ताइवान होंगे। यदि हाँगकाँग एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का हिस्सा बनता है तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का एक कार्यालय चीन के विशेष प्रशासन क्षेत्र में भी अवस्थित होगा।

जहां अनेक एशियाई देश और कुछेक यूरोपीय देश इस बैंक के संस्थापक सदस्य हैं, वहीं अमरीका और जापान इस पहल में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने स्वयं को इससे दूर रखा है, जिसके हालांकि, कुछ कारण हैं। अमरीका और जापान, जो एशियाई विकास बैंक के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, हमेशा से चीन के नेतृत्व वाले इस एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की परियोजना वित्तपोषण में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के आधार पर इस बैंक की पारदर्शिता पर ही प्रश्न उठाते रहे हैं। यह गौरतलब है कि ताइवान और चीन के सहयोगी, उत्तर कोरिया ने 2015 के प्रारंभ में संभावित संस्थापक सदस्य (पीएएम) के

रूप में सदस्यता हेतु आवेदन किया था। तथापि, उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि तइवान की निविदा को अस्वीकार किए जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ताइवान का आवेदन इसकी स्थिति के आधार पर रद्द किया गया था। ताइवान के लिए आशा की किरण यह है कि यह बाद में सदस्यता के लिए फिर से आवेदन कर सकता है। उत्तरी कोरिया के मामले में तो इसकी बोली को सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह अपने देश की वित्तीय तथा आर्थिक तस्वीर की विस्तृत पृष्ठभूमि उपलब्ध नहीं करा सका।

जहां तक एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के स्वरूप का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि यह बैंक चीन के 'संचालन' वाले 'एशियाई चेहरे' को प्रदर्शित करता है। यह बटुए की ताकत से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, क्योंकि कुल पूंजी का तीन चौथाई हिस्सा एशिया से आएगा। वास्तव में, चीन इस बैंक का सबसे बड़ा हिस्सेदार है जिसकी कुल पूंजी 30 अरब अमरीकी डॉलर है। इसलिए, किसी एक राष्ट्र की हिस्सेदारी के संबंध में, अर्थव्यवस्था का आकार और अंशदान की मात्रा इस बैंक में उसकी हिस्सेदारी का कोटा तय करेगी। उदाहरण के लिए, चीन, भारत, और रूस तीन सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 30.34 प्रतिशत, 8.52 प्रतिशत और 6.66 प्रतिशत है। इनके मतों की हिस्सेदारी क्रमशः 26.06 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 5.92 प्रतिशत परिकलित की गई है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में चीन की हिस्सेदारी, उसके इस आश्वासन के बावजूद कि वह ऐसी शक्तियां रखने का इच्छुक नहीं है, उसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर वीटो पावर देगी।[4]

जहां तक इसके काम-काज का प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) एक आधुनिक ज्ञान-आधारित संस्था, एशिया में अवसंरचना तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देगी जिनमें ऊर्जा तथा विद्युत, पर्यावरणीय सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास, यातायात एवं दूरसंचार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी विकास तथा संभारतंत्र आदि शामिल हैं।[5]

क्षेत्र हेतु निहितार्थ

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) को पश्चिम के प्रभुत्व वाली वित्तीय संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। सुधारों की धीमी गति, दीर्घकालिक नौकरशाही बाधाओं और पहले से मौजूद वित्तीय संस्थाओं में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, जहां विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर क्रमशः अमरीका और यूरोप का वर्चस्व माना जाता है वहीं एशियाई विकास बैंक जापानी वर्चस्व वाली वित्तीय संस्था है, जो चीन के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखती। चीनी दृष्टिकोण से, चीन के लिए ऐसी क्षेत्रीय आर्थिक संरचना या ढांचे को आगे बढ़ाने का औचित्य बनता है, क्योंकि एशियाई

विकास बैंक में जहां जापान और अमरीका क्रमशः 15.67 प्रतिशत और 15.56 प्रतिशत हिस्सेदारियों के साथ सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, वहीं चीन की हिस्सेदारी केवल 6.47 प्रतिशत तक ही सीमित है। यहां तक कि अन्य एशियाई देशों विशेषकर छोटे देशों का वैश्विक वित्तीय प्रणाली तथा संस्थाओं में ज्यादा बोलबाला नहीं है।

माना जा रहा है कि चीनी नेतृत्व वाली यह पहल बीजिंग के दोहरे प्रयोजन को पूरा करेगी:

- पहली बात, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना चीन की आर्थिक कूटनीति की एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस बैंक से एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में सुविधा होगी, यह न केवल चीन को अपने क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभाव जमाने में सहायता देगा, बल्कि चीन की 'एक पट्टी, एक सड़क' पहल को प्रोत्साहित करने में भी रचनात्मक भूमिका निभाएगा। सभी संभावनाओं में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का उचित उपयोग प्राचीन रेशम मार्ग (जिसे अब रेशम मार्ग आर्थिक पट्टी का नाम दिया गया है) के पुनरूद्धार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास का वित्तपोषण करने और इसके (चीन के) प्रस्तावित समुद्री रेशम मार्ग (एमएसआर) के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना है कि चीन 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु एक अन्य बैंक की स्थापना का इरादा रखता है। इस समुद्री रेशम मार्ग (एमएसआर) बैंक की स्थापना लगभग 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से किए जाने की आशा है। सारांशतः, यदि चीन के समुद्री रेशम मार्ग (एमएसआर) के विकास के लिए अलग से एक बैंक स्थापित हो जाता है तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) इस परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नए बैंक के साथ मिलकर काम करेगा।

- दूसरी बात, चीन ने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) नया विकास बैंक की भी पहल की और यह एक अन्य क्षेत्रीय बैंक एससीओ (संघाई सहयोग संगठन) विकास बैंक के लिए भी जोर लगा रहा है। यह रोचक है कि दोनों ही क्षेत्रीय बैंकों के मुख्यालय शंघाई में होंगे। कदाचित, चीन इस क्षेत्रीय वित्तीय फ्रेमवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लक्ष्य की प्राप्ति करना और एशियाई अर्थव्यवस्था को पश्चिम के वर्चस्व से मुक्त करना चाहता है। चीन का उद्देश्य एक आर्थिक संरचना की स्थापना करना है, जो इसकी आर्थिक शक्ति और निर्णयों के इर्द-गिर्द घूमेगी। चीन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की क्षमता एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार करार (एफटीएपी) पहल को सफल बनाने में निहित है, जो अमरीका-नीत प्रशांत-पार भागीदारी (टीटीपी) और एटलांटिक-पार व्यापार तथा निवेश भागीदारी (टीटीआईपी) से प्रतिस्पर्धा करता है। जहां टीटीआईपी ज्यादा प्रगति करने में सक्षम नहीं है, वहीं टीपीपी भी बाधाओं का सामना

कर रहा है क्योंकि इसके सदस्य देशों जैसे कि जापान, मलेशिया और वियतनाम के लिए भी इस करार के व्यापक लाभों पर अपने घरेलू क्षेत्रों को संतुष्ट करना कठिन हो रहा है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के लिए इस क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक निहितार्थ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक संरेखण के साथ-साथ, यह बैंक उस तरीके को भी प्रभावित करेगा, जिस तरह इस क्षेत्र के देश अपने कार्यनीतिक हितों तथा खतरों को समझते हैं। एशियाई शक्तियों, विशेष रूप से चीन की ज्यादा भागीदारी (स्टेक) होने से शायद इस क्षेत्र में अधिक परस्पर निर्भरता आएगी। यद्यपि यह अनुमान लगाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि यह पहल कितने आगे तक जाएगी; इस बात की बहुत संभावना है कि इस क्षेत्र के देश, जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति परखी जाती है, उस तरीके को नए सिरे से परखेंगे। इस संदर्भ में ह्यू वाइट तर्क देते हैं, "एक क्षण के लिए भी यह अनुमान न लगाएं कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) केवल अर्थव्यवस्था मात्र के लिए है। दशकों से अमरीका की कूटनीति और राजनीतिक प्रमुखता विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में वाशिंगटन की प्रमुख भूमिका से रेखांकित होती रही है। इसलिए अमरीकी जानते हैं कि एशिया में न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राजनैतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी चीन के प्रभाव के विस्तार में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) कितना प्रभावी साबित हो सकता है।"[6]

स्पष्ट है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) जब भी कार्य करने लगेगा, यह चीन को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। यह बैंक अन्य सदस्य देशों, विशेषकर जिन्हें चीन के ज्यादा करीब माना जाता है, के लिए भी लाभप्रद परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, विकासशील एशियाई देशों का इस बैंक में अब ज्यादा बोलबाला होगा। इसके अतिरिक्त, इस बैंक के मुख्य उद्देश्य को देखते हुए अवसंरचनात्मक विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्रगामी (*फास्ट-ट्रैक मोड* पर) होगी।

तथापि, चीन के प्रभुत्व के संबंध में आशंकाएं और अनिश्चितताएं अभी भी मंडरा रही हैं। यह आशंका होना कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) पर चीन का प्रभुत्व होगा, स्वाभाविक है। ऐसा विशेषकर तब सच प्रतीत होता है जब सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति में असमानता को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का सकल घरेलू उत्पाद जहां 10.36 खरब अमरीकी डॉलर है वहीं एक अन्य सदस्य देश कजाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद मात्र 8.5 अरब अमरीकी डॉलर है।

जहां पहले अमरीका ने इस बैंक के संबंध में अविश्वास प्रदर्शित किया था, वहीं अब उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रतीत होता है। 31 मार्च को अमरीकी वित्त सचिव (ट्रेजरी सेक्रेटरी) जॉक लियू ने कहा,

"अमरीका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास संरचना में नए संस्थानों के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार है।"[7] ऐसी संभावनाएं हैं कि चीन अमरीका को (बैंक की) गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए राजी करने का प्रयास कर सकता है। इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है और अमरीका के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में शामिल होने के संबंध में वार्ताओं को सितम्बर 2015 में राष्ट्रपति शी के अमरीकी दौरे के समय महत्व दिया जा सकता है। आगे चलकर अमरीका को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में शामिल होने पर विचार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से एकीकृत चीन अमरीका के भी हित में है। फिर भी अगर अमरीका एआईआईबी में शामिल होता है तब भी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में चीन के नेतृत्व के संबंध में स्थिति अस्पष्ट बनी रहेगी।

जहां तक भारत का प्रश्न है, चीन की प्रस्तावित परियोजनाओं और चीन-नीत पहलों को स्वीकार करते समय इसका रवैया सावधान रहने का रहा है। हालांकि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के संबंध में स्थिति तुलनात्मक रूप से भिन्न है। यह व्यवस्था भारत के हितों के अनुकूल है, क्योंकि चीन के बाद इस बैंक में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार होने के कारण एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में उपाध्यक्ष का पद प्राप्त करने की भारत की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। दूसरी बात, वर्तमान में, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का उद्देश्य एशियाई बुनियादी ढांचों के विकास पर ज्यादा ध्यान देना है। घरेलू अवसंरचनाओं का निर्माण और विकासात्मक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में भारत की स्वभाविक रूचि रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लिए अंतरा-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संपर्क का विकास एक प्राथमिकता बन गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में यह संकेत दिया गया था कि भारत को सतत विकास सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं से उबरने के लिए बुनियादी ढांचों में कम से कम एक खरब अमरीकी डॉलर निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक संस्थापक सदस्य के रूप में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) में भारत का शामिल होना इसकी बुनियादी ढांचों के विकास में योगदान देगा और इसी उदेश्य के लिए निवेश की कमी की समस्या को दूर करेगा। भारत अपनी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) अभी शुरूआती स्तर पर है और वर्ष 2016 तक इसके पूरी तरह से कार्यरत हो जाने की आशा है। रोचक तथ्य है कि अब तक 57 भागीदार एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) संबंधी वार्ताओं में शामिल हैं और इसे विश्व भर के देशों से और ज्यादा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। यदि और अधिक सदस्यों को शामिल किया जाता है तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

(एआईआईबी) के सदस्यों की संख्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सदस्यों से अधिक हो जाएगी, जो वर्तमान में 67 हैं। यह निश्चित रूप से मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से असंतुष्ट देशों को आशा देता है। वर्ष 2016 में यूरोपीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक (ईबीआरडी) तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की प्रथम संयुक्त परियोजना की संभावना के संबंध में ईबीआरडी की घोषणा के साथ ही एआईआईबी को पहले ही महत्व मिल रहा है।

यह देखते हुए कि समकालीन समय में एशियाई क्षेत्रवाद में संपर्क एक नया मंत्र है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) का उद्देश्य एशियाई अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। तथापि, अलग-अलग देशों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु धन उपलब्ध कराने से लेकर उप-क्षेत्रीय तथा अंतर-क्षेत्रीय स्तरों पर संपर्क सुदृढ़ करने में उन्हें सहायता देने तक कार्यक्षेत्र को विस्तार दिए जाने की जरूरत है। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि बेहतर जानकारी के अभाव में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं हैं, इस मुकाम पर एआईआईबी के सटीक भविष्य पथ (ट्रैजेक्टरी) की भविष्यवाणी करना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। तथापि, इसकी बहुत संभावना है कि ऐसे प्रयास एशिया को बृहत्तर क्षेत्रीय अर्थिक एकीकरण के मार्ग पर ले जाऐंगे। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) को सफल बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि चीन, विशेषकर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर, अपने हठी व्यवहार के संबंध में एआईआईबी के सदस्यों के संदेह को दूर करने का प्रयत्न करे और एआईआईबी पर संभावित प्रभुत्व के संबंध में दुविधा को दूर करने के लिए कदम उठाए।

***

डॉ. राहुल मित्रा विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

समाप्ति नोट:

1" चीन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की तैयारी संबंधी वार्ता तेज करने के लिए तैयार: प्रधान मंत्री", सिन्हुआ, 10 अप्रैल, 2015.http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/10/c_133251336.htm, (2 जून, 2015 को एक्सेस किया गया)।

2 "एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक", AIIB,. http://www.aiibank.org/html/aboutus/AIIB/, (1 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया)।

3 मैलकम कुक, "दो एशिया: एआईआईबी बनाम एडीबी", स्ट्रेट्स टाइम्स, 5 जून, 2015,. http://www.straitstimes.com/opinion/two-asias-aiib-v-adb, (6 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया)।

4 " भारत सहित पचास देशों ने चीन के नेतृत्व वाली एआईआईबी संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए", इकोनॉमिक टाइम्स, 30 जून, 2015 http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47862160.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, (1 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया)।

5 "एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक", AIIB,. http://www.aiibank.org/html/aboutus/AIIB/, (1 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया)।

6 ह्यूग व्हाइट, "एआईआईबी: संतुलन में अमेरिका का प्रभाव", स्ट्रेट्स टाइम्स, 29 अक्टूबर, 2014,. http://www.straitstimes.com/opinion/aiib-americas-influence-in-the-balance, (2 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया)।

7 "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संरचना पर एशिया सोसायटी उत्तरी कैलिफोर्निया में सचिव ल्यू की टिप्पणियां और उच्च लक्ष्य का महत्व", अमरीकी राज्य-कोष विभाग, 31मार्च, 2015, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl10014.aspx, (2 जुलाई, 2015 को एक्सेस किया गया।)।